मैंसर्स डोजको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

मैंसर्स डूसन इन्फ्राकोर कंपनी लिमिटेड

(मध्यस्थता याचिका की संख्या 5/2008)

अक्टूबर 08, 2010

(वी.एस.सिरपुरकर, जे.जे.,)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-धारा 11 (6) मध्यस्थ की नियुक्ति- भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनी के बीच वितरण समझौता-पार्टियों के बीच विवाद-मध्यस्थता खंड- अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता आवेदन अंतर्गत धारा 11 (6) मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए- प्रार्थना पत्र की पोषनीयता- घोषित किया गयाः डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौता अधिनियम के भाग प् को छोड़कर पार्टियों के बीच स्पष्ट समझौते को बताता है- समझौते के अनुच्छेद 22 और 23 की भाषा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला कानून कोरियाई कानून होगा और मध्यस्थता का स्थान कोरिया में केवल सियोल में होगा- लागू किए जाने वाले मध्यस्थता के नियम इंटरनेशनल चौंबर ऑफ कॉमर्स के नियम थे - इस प्रकार धारा 11 (6) लागू नहीं- सुप्रीम कोर्ट के पास अंतर्गत धारा 11(6) के अधीन मध्यस्थ नियुक्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

एक भारतीय कंपनी और एक विदेशी कंपनी ने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौता किया। दोनों कंपनियों के बीच विवाद खड़ा हो गया समझौते में मध्यस्थता खंड के संदर्भ में, भारतीय कंपनी-याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नोटिस जारी किया। हालाँकि, मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत तत्काल याचिका दायर की। याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहाः 1. जब तक भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को विशेष रूप से कम से कम भाग प् से बाहर नहीं रखा जाता है तब तक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 जिसके तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति है, अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत आती है, इस न्यायालय के पास मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र होगा, भले ही मध्यस्थता विदेशी कानून द्वारा शासित हो।

भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एस.ए. और अन्य। 2002(4) एससीसी 105 लिंडटेल टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम डब्ल्यू.एस. एटकिन्स रेल लिमिटेड 2008 (10) एससीसी 308, साईटेशन इन्फोवेयर्स लिमिटेड बनाम इक्विनॉक्स कॉर्पोरेशन 2009 (7) एससीसी 220, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बनाम सिंगर कंपनी और अन्य। 1992 (3) सी एससीसी 551, सीएमसी लिमिटेड बनाम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और अन्य। 2007 (10) सेकंड 751-संदर्भित किये गये।

2. विवाद की मध्यस्थता, मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाले कानून के संदर्भ में निर्धारित की जानी है और मध्यस्थता कार्यवाही क्यूरियल कानून के अनुसार संचालित की जानी है।

सुमितोमो हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ओएनजीसी लिमिटेड और अन्य। 1998 (1) धारा 305 -पर भरोसा किया गया।

मस्टिल और बॉयड द्वितीय संस्करण द्वारा इंग्लैंड में वाणिज्यिक मध्यस्थता का कानून और अभ्यास प्रस्तुत किया गया।

3.1 डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते के अनुच्छेद 23 को अनुच्छेद 22 और विशेष रूप से अनुच्छेद 22.1 की पृष्ठभूमि में पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 22.1 की भाषा से यह स्पष्ट है कि संपूर्ण समझौता कोरिया गणराज्य के कानूनों के अनुसार शासित और समझा जाएगा। अनुच्छेद 23.1 की भाषा को अनुच्छेद 22.1 के आलोक में देखने पर यह स्पष्ट है कि पक्ष इस बात पर सहमत थे कि उनके बीच समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों को अंततः सियोल, कोरिया में मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाएगा। लागू किए जाने वाले मध्यस्थता के नियम इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के नियम थे। इससे प्रथम दृष्टया यह आभास होता है कि मध्यस्थता का स्थान केवल सियोल, दक्षिण कोरिया में था।(पैरा12,13,)[268-डी-ई 270-ई-एफ,]

3.2 यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 23 में ब्रैकेटेड हिस्से

के कारण ऐसी अन्य जगह जहां पार्टियां लिखित रूप में सहमत हो सकती हैं, स्थान कहीं और भी हो सकता है, इस प्रकार, कोई स्पष्ट नहीं है अधिनियम के भाग प् का बहिष्कार किसी ब्रैकेट को मुख्य उपवाक्य को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ब्रैकेटेड भाग केवल आगे की व्याख्या के प्रयोजन के लिए है। ब्रैकेटेड भाग केवल मध्यस्थता न्यायाधिकरण और मध्यस्थता की कार्यवाही संचालित करने के लिए पार्टियों की सुविधा के लिए है, लेकिन ब्रैकेटेड भाग, किसी भी तरह से, मध्यस्थता के स्थान को नहीं बदलता है, जो केवल सियोल है, कोरिया। भाषा स्पष्ट रूप से अधिनियम के भाग प् के स्पष्ट बहिष्कार का संकेत देती है। ब्रैकेट वाले हिस्से का लाभ नहीं उठाया जा सकता. अनुच्छेद में ब्रैकेटेड भाग पार्टियों की सुविधा के लिए था, यदि वे सियोल, कोरिया के अलावा कहीं और मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करना चाहते हैं।(पैरा 12 और 13,)[270-एफ-एच, 271-ए-बी 274-बी-सी,]

3.3 पार्टियों के बीच वितरण समझौते के अनुच्छेद 22 और 23 की एक स्पष्ट भाषा अधिनियम के भाग प् को छोड़कर पार्टियों के बीच एक स्पष्ट समझौते को दर्शाती है। चूंकि अनुच्छेद 23.1 की व्याख्या से पता चलता है कि कानून को नियंत्रित करना मध्यस्थता कोरियाई कानून होगी और मध्यस्थता का स्थान कोरिया में सियोल होगा, अधिनियम की धारा 11 (6) की प्रयोज्यता और उस प्रावधान के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति

का कोई सवाल नहीं होगा। (पैरा13,) [274-सी-जी,]

भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एस.ए. और अन्य। 2002(4) एससीसी 105 य लिंडटेल टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम डब्ल्यू.एस. एटकिंस रेल लिमिटेड 2008(1) एससीसी 308 य साईटेशन एनफोवेयर्स लिमिटेड बनाम इक्विनॉक्स कॉरपोरेशन 2009 (7) एससीसी 220 लागू माना गया। नेवीरा अमोजोनिका पेरुआफला एस.ए. बनाम कंपेनिया इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू 1998 खंड 1 लॉयड्स लॉ रिपोर्ट्स- का उल्लेख किया गया है।

केस लॉ संदर्भ

1998(1) धारा 305	पर भरोसा किया गया।	पैरा 12
1992(3) सेकंड 551	का उल्लेख है।	पैरा 12
2007(10) धारा 751	का उल्लेख किया गया है।	पैरा 13
1998 खंड 1 लॉयड्स लॉ रिपोर्ट को संदर्भित किया गया।		पैरा 13
2002(4) धारा 105	को अनुचित ठहराया गया।	पैरा 13
2008 (10) धारा 308	को अनुचित ठहराया गया।	पैरा 13
2009 (7) धारा 220	को अनुचित ठहराया गया।	पैरा 13

मूल क्षेत्राधिकार: मध्यस्थता याचिका की संख्या 5/2008 की ।

मोहन और अभिषेक कौशिक याचिकाकर्ता के लिए.

गुरुकृष्ण कुमार और श्रीकला गुरुकृष्ण कुमार। प्रतिवादी की ओर से

न्यायालय का निर्णय वी.एस. सिरपुरकर न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

1. यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम(इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 11(6) के तहत एक याचिका है।याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है, प्रतिवादी सियोल, दक्षिण कोरिया में निगमित एक कंपनी है जिसका मुख्य स्थान सियोल है। इन दोनों कंपनियों के बीच विवाद एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते से उत्पन्न हुआ है जो 2.2.2004 को पार्टियों के बीच निष्पादित किया गया था। इसके द्वारा, याचिकाकर्ता को अपने उत्पादों जैसे एक्सकेवेटर, व्हील लोडर आदि के लिए भारत और भूटान में प्रतिवादी का विशेष वितरक था। डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते का अनुच्छेद 23 मध्यस्थता द्वारा विवादों के समाधान का प्रावधान करता है। चूंकि विवाद दोनों कंपनियों के बीच उत्पन्न हुआ है और चूंकि एक कंपनी सियोल, दक्षिण कोरिया में स्थित है, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मानते हुए वर्तमान याचिका दायर की गई है। पार्टियों के बीच कोई विवाद नहीं है कि यह डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते के अनुच्छेद 23 के मध्यस्थता खंड के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता होगी।

2. इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि पार्टियों के बीच विवाद

उत्पन्न हुआ है जिसके कारण प्रतिवादी ने उनके बीच हुए समझौते को समाप्त करने का आशय है। विवादों के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दिनांक 01.09.2007 को नोटिस जारी किया। हालाँकि, ऐसा नहीं होने पर, वर्तमान याचिका आवश्यक हो गई है।

3. चूंकि पार्टियों ने मध्यस्थता खंड के अस्तित्व के बारे में विवाद नहीं किया है, विवादों के अस्तित्व के कारण एक जीवंत मुद्दा, किसी भी निष्कर्ष को दर्ज करने का कोई सवाल ही नहीं होगा। हालाँकि, रिकॉर्ड को स्पष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे इस प्रकार हैंः-

1. क्या समय से पहले और कथित तौर पर प्रतिवादी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते की समय से पहले और एकतरफा समाप्ति कानून में वैध है।

2. क्या डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते को समाप्त करने के लिए प्रतिवादी द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्क कानून में वैध हैं

3. क्या प्रतिवादी वर्ष के मध्य में उत्पादों की कीमत एकतरफा बढ़ाने का अधिकार रखता है।

4. क्या प्रतिवादी याचिकाकर्ता को आपूर्ति को एकतरफा नियंत्रित करने का अधिकारी है।

5. क्या प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को 10 साल के लिए राष्ट्रीय डीलर के रूप में नियुक्त करने के अपने वादे से रोका गया है

6. क्या प्रतिवादी उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ता को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी हैं।"

4. याचिका का प्रतिवादी की ओर से प्रतिवाद किया जाता है जो पोषणीयता के आधार पर इसका विरोध करता है। प्रतिवादी के अनुसार, पार्टियों के बीच समझौते के अनुसार केवल इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के मध्यस्थता के नियम लागू होंगे। प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय के पास मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 11(6) के तहत कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा , विशेष रूप से, क्योंकि अनुच्छेद 22 और 23 में विशेष रूप से सहमति व्यक्त की गई है जो इस प्रकार हैंः

"अनुच्छेद 22. शासित विधि - 22.1: यह समझौता कोरिया गणराज्य के कानूनों के अनुसार शासित और निरूपित समझा जाएगा।

अनुच्छेद 23. मध्यस्थता - 23.1: इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को अंततः सियोल, कोरिया

(या ऐसे अन्य स्थान जहां पार्टियां लिखित रूप में सहमत हो सकती हैं) में मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाएगा, उस समय लागू समझौते के नियमों के अनुसार इंटरनेशनल चौंबर ऑफ कॉमर्स (जोर दिया गया)''

5. इसलिए, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके भारत में वर्तमान कार्यवाही को बनाए रखने का हकदार नहीं होगा। प्रतिवादी विशेष रूप से याचिकाकर्ता के रुख पर विवाद करता है कि समझौते में मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाले भारतीय प्रक्रियात्मक कानून की प्रयोज्यता से इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रतिवादी ने विशेष रूप से यह भी तर्क दिया कि भारतीय न्यायालयों और इस अधिनियम की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। उनका मूल तर्क यह था कि प्रासंगिक धाराओं के तहत भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से समाप्त हो गया है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि खंड 33 में यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स, पेरिस के मध्यस्थता के नियमों के संदर्भ में सियोल में मध्यस्थता द्वारा विवादों को निपटाने के लिए एक स्पष्ट समझौता है। प्रतिवादी ने अपने प्रतिवाद में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के मध्यस्थता नियमों के अनुच्छेद 4 पर भरोसा किया है।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि पहले मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष

अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें मध्यस्थ कार्यवाही के समापन तक उत्तरदाताओं, उनके लोगों और एजेंटों को किसी भी तरह से भारत में अपने उत्पादों से सीधे निपटने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। यह बताया गया कि 8.5.2008 को उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा का एक पक्षीय आदेश दिया गया था। हालाँकि, जब प्रतिवादी ने एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया, तो प्रतिवादी ने विशेष रूप से तर्क दिया था कि चेन्नई की अदालतों के पास आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह बताया गया कि निषेधाज्ञा हटाने के प्रतिवादी के आवेदन को मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9.6.2008 द्वारा अनुमति दे दी थी। हालाँकि, अपने आदेश में, ऐसा लगता है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न को पक्षों द्वारा बाद के चरण में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। इसने एक निष्कर्ष भी दर्ज किया कि निषेधाज्ञा आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र के प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं था। प्रतिवादी ने धारा 9 के तहत आवेदन के साथ उक्त आदेश इस न्यायालय के समक्ष दायर किया है ।

7. उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों से, एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या इस न्यायालय के लिए न्यायोचित और उचित होगा कि अधिनियम की धारा 11

(6) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र है।

8. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री मोहना ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों, अर्थात् भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एसए और अन्य पर बहुत अधिक भरोसा किया। (2002(4) एससीसी 105), इंडटेल टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम डब्ल्यूएस एटकिंस रेल लिमिटेड। (2008 (10) एससीसी 308) और साइटेशन इन्फोवेयर्स लिमिटेड बनाम इक्विनॉक्स कॉर्पोरेशन (2009 (7) एससीसी 220)। उनके अनुसार, इन सभी मामलों ने कानून को यह कहते हुए सुलझा लिया है कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में भी, जो भारत से बाहर आयोजित किया जाना है और विदेशी कानून द्वारा शासित होना है, अधिनियम के भाग प् के प्रावधान तब भी लागू होंगे जब तक कि पक्षकार समझौते द्वारा, व्यक्त या निहित, अधिनियम के भाग प् के सभी या किसी भी प्रावधान को बाहर करता है। उन्होंने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बनाम सिंगर कंपनी और अन्य मामले में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। (1992 (3) एससीसी 551)। न्यायालय का ध्यान सीएमसी लिमिटेड बनाम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एवं अन्य मामले में निर्णय की भाषा की ओर भी आकर्षित किया गया। (2007 (10) एससीसी 751)। कुछ अन्य निर्णय भी हैं जिन पर विद्वान वकील भरोसा करते हैं। हालाँकि, मुख्य विवाद भाटिया

इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एसए और अन्य मामले में निर्णय के पैराग्राफ 32 पर आधारित है। (ऊपर उद्धृत) साथ ही इंडटेल टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम डब्ल्यूएस एटकिन्स रेल लिमिटेड के फैसले का पैराग्राफ 36 भी। (ऊपर उद्धृत), जहां भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एसए और अन्य के फैसले पर भरोसा किया गया था। (ऊपर उद्धृत) जो तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है। न्यायालय का ध्यान उस फैसले के पैराग्राफ 30, 31 और 36 के साथ-साथ पैराग्राफ 35, 38 की ओर भी आकर्षित किया गया था, जहां भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एसए और अन्य में निर्णय दिया गया था। (उपर्युक्त उद्धृत) पर भरोसा किया गया था। इन तीनों निर्णयों से, यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को विशेष रूप से बाहर नहीं रखा जाता है, तब तक अधिनियम का कम से कम भाग प् जिसके तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति है, अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत आता है, यह न्यायालय उसके पास मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र होगा, भले ही मध्यस्थता विदेशी कानून द्वारा शासित हो।

9. हालांकि, प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री गुरुकृष्ण कुमार ने इस याचिका का विरोध करते हुए आग्रह किया कि इस मामले में और विशेष रूप से पैराग्राफ 23 में इस तरह के बहिष्करण को विशेष रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने खंड 23 की भाषा की तुलना, विशेष रूप से, क्षेत्राधिकार

संबंधी कारण से की है जो कि साइटेशन इन्फोवेयर्स लिमिटेड बनाम इक्विनॉक्स कॉर्पोरेशन (सुप्रा) में विचाराधीन था। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 23 में रेखांकित किए गए हिस्से की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि मध्यस्थता का स्थान पार्टियों की पसंद के अनुसार कहीं और हो सकती है। उन्होंने बताया कि ब्रैकेटेड भाग केवल सियोल के अलावा कहीं और मध्यस्थता की कार्यवाही आयोजित करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से है। हालाँकि, इसे अनुच्छेद 23 के मुख्य खंड को ओवरराइड करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एसए और अन्य में निर्धारित कानून। (ऊपर उद्धृत) और उसके बाद के निर्णय लागू नहीं होंगे। विद्वान वकील ने सुमितोमो हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ओएनजीसी लिमिटेड और अन्य पर भरोसा किया। (1998 (1) एससीसी 305)। उन्होंने नवीरा अमोजोनिका पेरुआना एसए बनाम कंपेनिया इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू (1998) खंड 1 लॉयड्स लॉ रिपोर्ट्स के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भी भरोसा किया।

10. विद्वान वकील ने ईमानदारी से तर्क दिया कि मध्यस्थता की कानूनी सीट और कार्यवाही आयोजित करने के लिए भौगोलिक रूप से सुविधाजनक स्थान के बीच अंतर है और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की एक सामान्य विशेषता है। उन्होंने रेडफर्न और हंटर के एक अंश पर भी

भरोसा किया जो इस प्रकार हैरू

‘‘पिछली चर्चा इस आधार पर रही है कि मध्यस्थता का केवल एक ‘स्थान’ है। यह पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से चुना गया स्थान होगा और इसे मध्यस्थता समझौते या संदर्भ की शर्तों या मिनटों में निर्दिष्ट किया जाएगा। कार्यवाही की या किसी अन्य में मध्यस्थता की ‘सीट’ की जगह थी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपनी सभी बैठकें या सुनवाई मध्यस्थता के स्थान पर आयोजित करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में अक्सर कई लोगों को शामिल किया जाता है अलग-अलग राष्ट्रीयताएं, अलग-अलग देशों से। इन परिस्थितियों में, किसी मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए मध्यस्थता के निर्दिष्ट स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर अपनी सुविधा के लिए या सुविधा के लिए बैठक आयोजित करना या यहां तक कि सुनवाई करना किसी भी तरह से असामान्य नहीं है। पक्ष या उनके गवाह... एक देश में बैठे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए दूसरे देश में सुनवाई करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है- उदाहरण के लिए साक्ष्य लेने के उद्देश्य से... ऐसी परिस्थितियों में, मध्यस्थ

न्यायाधिकरण का प्रत्येक कदम इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता की स्थिति बदल जाती है। मध्यस्थता की सीट वह स्थान है जिस पर शुरू में पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से सहमति व्यक्त की गई थी'' (जोर दिया गया)

11. उनके अनुसार, पार्टियों के बीच समझौते के अनुसार, यह स्पष्ट है कि पार्टियों ने अनुबंध के उचित कानून और मध्यस्थता समझौते को सियोल, दक्षिण कोरिया में मध्यस्थता की सीट के साथ कोरियाई कानून और मध्यस्थता कानून के रूप में चुना है। इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापक नियमों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है।

12. इन परस्पर विरोधी दावों की पृष्ठभूमि में, सवाल यह उठता है कि अनुच्छेद 23 की सही व्याख्या क्या है। इस अनुच्छेद 23 को अनुच्छेद 22 और विशेष रूप से अनुच्छेद 22.1 की पृष्ठभूमि में पढ़ना होगा। अनुच्छेद 22.1 की भाषा से यह स्पष्ट है कि संपूर्ण समझौता कोरिया गणराज्य के कानूनों के अनुसार शासित समझा जाएगा। यही कारण है कि प्रतिवादी ने सुमितोमो हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ओएनजीसी लिमिटेड और अन्य में निर्धारित कानून पर बहुत अधिक भरोसा किया। (सुप्रा उद्धृत)। यह निर्णय इस प्रस्ताव पर पूर्ण अधिकार है कि विवाद की मध्यस्थता मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाले कानून के संदर्भ में निर्धारित की जानी है और मध्यस्थता कार्यवाही क्यूरियल कानून के

अनुसार संचालित की जानी है। इस न्यायालय ने, उस फैसले में, मस्टिल और बॉयड (इंग्लैंड में वाणिज्यिक मध्यस्थता का कानून और अभ्यास, दूसरा संस्करण) पर भरोसा करते हुए, पैराग्राफ 15 में देखा कि जहां संदर्भ के आचरण को नियंत्रित करने वाला कानून अंतर्निहित मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले कानून से अलग है। समझौता, न्यायालय यह देखने के लिए मध्यस्थता समझौते को देखता है कि क्या विवाद मध्यस्थता योग्य है, फिर क्यूरियल कानून को यह देखने के लिए कि संदर्भ कैसे संचालित किया जाना चाहिए और फिर परिणामी पुरस्कार को प्रभावी करने के लिए पहले कानून पर लौटता है। अनुच्छेद 16 में, इस न्यायालय ने, बिना किसी अनिश्चित शब्दों के, घोषणा की कि जो कानून पुरस्कार दाखिल करने, उसके प्रवर्तन और उसे रद्द करने पर लागू होगा वह मध्यस्थता समझौते और उस समझौते के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाला कानून होगा। न्यायालय ने मस्टिल और बॉयड की टिप्पणियों पर इस आशय से भरोसा किया:-

> "इसलिए, यह देखा जा सकता है कि मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, कम से कम सिद्धांत रूप में, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक कानूनों को लागू करने की मांग कर सकती हैं-
>
> 1. अनुबंध का उचित कानून, यानी अनुबंध को

नियंत्रित करने वाला कानून जो पार्टियों के मूल अधिकारों का निर्माण करता है, जिसके संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है।

2. मध्यस्थता समझौते का उचित कानून, यानी विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने और एक पुरस्कार का सम्मान करने के लिए पार्टियों के दायित्व को नियंत्रित करने वाला कानून।

3. कोरियाई कानून, यानी व्यक्तिगत संदर्भ के आचरण को नियंत्रित करने वाला कानून।

1. मध्यस्थता समझौते का उचित कानून मध्यस्थता समझौते की वैधता को नियंत्रित करता है, सवाल यह है कि क्या कोई विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे में है मध्यस्थता के नोटिस की वैद्यता न्यायाधिकरण का संविधान यह प्रश्न कि क्या कोई निर्णय मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में आता है। अवॉर्ड की औपचारिक वैधताय प्रश्न यह है कि क्या पार्टियों को भविष्य के विवादों में मध्यस्थता करने के किसी भी दायित्व से मुक्त कर दिया गया है।

2. कोरियाई कानून यह नियंत्रित करता है जिस तरीके

से संदर्भ संचालित किया जाना है मध्यस्थ की प्रक्रियात्मक शक्तियां और कर्तव्यय साक्ष्य के प्रश्नय अनुबंध के उचित कानून का निर्धारण.

3. संदर्भ का उचित कानून नियंत्रित करता है यह प्रश्न कि क्या पार्टियों को व्यक्तिगत विवाद के संदर्भ को जारी रखने के अपने दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। ''(जोर दिया गया) मस्टिल और बॉयड का निम्नलिखित पैराग्राफ निर्णय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है यह मामलाः- ''स्पष्ट समझौते की अनुपस्थिति में, एक मजबूत प्रथम दृष्टया धारणा है कि पार्टियां कोरियाई कानून को मध्यस्थता की 'सीट' का कानून बनाने का इरादा रखती हैं, यानी वह स्थान जहां मध्यस्थता आयोजित की जानी है, इस आधार पर कि वह देश कार्यवाही से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। इसलिए पार्टियों द्वारा स्पष्ट विकल्प के अभाव में कोरियाई कानून का निर्धारण करने के लिए, मध्यस्थता के लिए समझौते का अर्थ लगाकर, मध्यस्थता की सीट निर्धारित करना सबसे पहले आवश्यक है।''

पैराग्राफ 15 और 16 में, इस न्यायालय ने ऊपर उद्धृत टिप्पणियों पर बहुत अधिक भरोसा किया है। यदि हम अनुच्छेद 23.1 की भाषा को

अनुच्छेद 22.1 के आलोक में देखें, तो यह स्पष्ट है कि पक्ष इस बात पर सहमत थे कि उनके बीच समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों को अंततः सियोल, कोरिया में मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि लागू किए जाने वाले मध्यस्थता के नियम इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के नियम थे। इससे प्रथम दृष्टया यह आभास होता है कि मध्यस्थता की सीट केवल सियोल, दक्षिण कोरिया में थी। हालाँकि, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री मोहना ने ब्रैकेटेड भाग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और तर्क दिया कि ब्रैकेटेड भाग के कारण "या ऐसी अन्य जगह जहां पार्टियां लिखित रूप में सहमत हो सकती हैं", स्थान अन्यत्र भी हो सकता है. इसी के आधार पर सुश्री मोहना ने तर्क दिया कि, इसलिए, अधिनियम के भाग प् का कोई स्पष्ट बहिष्कार नहीं है। इस तर्क को इस साधारण कारण से स्वीकार करना संभव नहीं है कि किसी ब्रैकेट को मुख्य खंड को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ब्रैकेटेड भाग केवल आगे की व्याख्या के प्रयोजन के लिए है। मेरी राय में, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गुरुकृष्ण कुमार का यह तर्क सही है कि ब्रैकेटेड भाग केवल मध्यस्थ न्यायाधिकरण औरध्या मध्यस्थता की कार्यवाही के संचालन के लिए पार्टियों की सुविधा के लिए है, लेकिन ब्रैकेटेड भाग, किसी भी तरह से, मध्यस्थता की सीट को नहीं बदलता है, जो केवल सियोल, कोरिया है। यह भाषा स्पष्ट रूप से अधिनियम के भाग प् के स्पष्ट बहिष्कार का संकेत देती है। यदि ऐसा

बहिष्करण है, तो भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एसए और अन्य में निर्धारित कानून। (ऊपर उद्धृत) होल्डिंग लागू होनी चाहिएः-

> ‘‘भारत से बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामलों में भाग 1 के प्रावधान तब तक लागू होंगे जब तक कि पक्ष समझौते से, व्यक्त या निहित, इसके सभी या किसी भी प्रावधान को बाहर नहीं कर देते। उस स्थिति में, पार्टियों द्वारा चुने गए कानून या नियम मान्य होंगे। भाग 1 में कोई भी प्रावधान, जो उस कानून या नियमों के विपरीत है या उससे बाहर है, लागू नहीं होगा।’’

यहां तक कि इंडटेल टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम डब्ल्यूएस एटकिन्स रेल लिमिटेड मामले में भी। (ऊपर उद्धृत), पार्टियों ने मध्यस्थता की सीट/स्थल सहित मध्यस्थता प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कानून को नहीं चुना था और इसलिए, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11(6) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया। उसमें विशेष रूप से पाया गया कि पार्टियों द्वारा स्पष्ट या परोक्ष रूप से अधिनियम के प्रावधानों का कोई बहिष्कार नहीं किया गया था, जो उस निर्णय के पैराग्राफ 37 में की गई टिप्पणियों से स्पष्ट है।

13. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री मोहना ने हालांकि, साइटेशन इन्फोवेयर्स लिमिटेड बनाम इक्विनॉक्स कॉरपोरेशन

(ऊपर उद्धृत) के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया। वहाँ भी, पार्टियाँ कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों द्वारा शासित होने पर सहमत हुई थीं। विद्वान वकील ने हमारा ध्यान समझौते के खंड 10.1 की ओर आकर्षित किया, जो निम्नानुसार हैरू -

> "10.1 शासी कानून यह समझौता कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किया जाएगा और इस समझौते या इसके विषय से संबंधित विवाद के मामलों, यदि कोई हो, को पारस्परिक रूप से सहमत मध्यस्थ के पास मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।"

सुश्री मोहना ने आगे कहा कि इस खंड की भाषा इस मामले में पार्टियों के बीच वितरण समझौते के अनुच्छेद 23.1 से काफी समान है, जबकि, प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री गुरुकृष्ण कुमार ने तर्क दिया कि दोनों की भाषा में आवश्यक अंतर है। खंड. उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 23.1 की भाषा, उद्धरण इन्फोवेयर्स लिमिटेड बनाम इक्विनॉक्स कॉरपोरेशन (ऊपर उद्धृत) के मामले में खंड 10.1 के विपरीत, स्पष्ट रूप से बताती है कि मध्यस्थता की सीट सियोल, कोरिया में होने पर सहमति हुई थी और इस प्रकार, अधिनियम के भाग प् का स्पष्ट बहिष्कार होगा। मेरी राय में, साइटेशन इन्फोवेयर्स लिमिटेड बनाम इक्विनॉक्स कॉर्पोरेशन (ऊपर उद्धृत) के मामले में और साथ ही इंडटेल टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

बनाम डब्ल्यूएस एटकिंस रेल लिमिटेड के मामले में उल्लिखित खंडों के बीच आवश्यक अंतर है। एक ओर (उपर्युक्त उद्धृत) और दूसरी ओर वर्तमान मामले में अनुच्छेद 23.1। श्री गुरुकृष्ण कुमार ने ठीक ही बताया कि कोष्ठक वाले भाग का लाभ नहीं उठाया जा सकता है, विशेष रूप से, नवीरा अमोजोनिका पेरुआना एसए बनाम कंपेनिया इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू (उद्धृत सुप्रा) के फैसले को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह कहा गया थारू -

> "सभी अनुबंध जो मध्यस्थता के लिए प्रदान करते हैं और एक विदेशी तत्व शामिल करते हैं, उनमें कानून की तीन संभावित प्रासंगिक प्रणालियाँ शामिल हो सकती हैं (ए) मूल अनुबंध को नियंत्रित करने वाला कानूनय (2) मध्यस्थता के समझौते और उस समझौते के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाला कानूनय (3)) मध्यस्थता के संचालन को नियंत्रित करने वाला कानून। अधिकांश मामलों में तीनों एक जैसे होंगे, लेकिन (1) अक्सर (2) और (3) से भिन्न होंगे और कभी-कभी, लेकिन शायद ही कभी, (2) भी हो सकते हैं (3)से भिन्न।"

बिल्कुल यही मामला यहाँ है। अनुच्छेद 23.1 की भाषा स्पष्ट रूप से बताती है कि सभी तीन कानून सियोल, कोरिया में मध्यस्थता की सीट के

साथ कोरिया गणराज्य के कानून हैं और मध्यस्थता इंटरनेशनल चौंबर ऑफ कॉमर्स के नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी। हालाँकि, कोष्ठक वाले भाग के संबंध में, यह देखा जाना चाहिए कि उस मामले में यह देखा गया था-

> "....यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नीचे दिए गए प्रस्तुतीकरण में मध्यस्थता की कानूनी "सीट" आदि को भौगोलिक रूप से सुविधाजनक स्थान या सुनवाई के लिए स्थानों के साथ भ्रमित किया गया है। यह अंतर आजकल अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की एक सामान्य विशेषता है और इसमें सहायक रूप से समझाया गया है रेडफर्न और हंटर निम्नलिखित अनुच्छेद में "मध्यस्थता का स्थान" शीर्षक के अंतर्गत:
>
> पिछली चर्चा इस आधार पर की गई है कि मध्यस्थता का केवल एक ही "स्थान" है। यह पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से चुनी गई जगह होगी और इसे मध्यस्थता समझौते या संदर्भ की शर्तों या कार्यवाही के मिनटों में या किसी अन्य तरीके से मध्यस्थता के स्थान या ष्सीटष् के रूप में नामित किया जाएगा। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अपनी सभी बैठकें या सुनवाई मध्यस्थता के स्थान पर आयोजित करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय

वाणिज्यिक मध्यस्थता में अक्सर कई अलग-अलग देशों के, कई अलग-अलग राष्ट्रीयताओं के लोग शामिल होते हैं। इन परिस्थितियों में, किसी मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए अपनी सुविधा के लिए या पार्टियों या उनके गवाहों की सुविधा के लिए, मध्यस्थता के निर्दिष्ट स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर बैठकें- या यहां तक कि सुनवाई - आयोजित करना किसी भी तरह से असामान्य नहीं है। ..... एक देश में बैठे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए दूसरे देश में सुनवाई करना अधिक सुविधाजनक हो सकता है - उदाहरण के लिए, साक्ष्य लेने के उद्देश्य से...ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्येक कदम मध्यस्थ न्यायाधिकरण का मतलब यह नहीं है कि मध्यस्थता की सीट बदल जाती है। मध्यस्थता की सीट वह स्थान बनी रहती है जिस पर प्रारंभ में पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से सहमति व्यक्त की गई थी।

जब कोई न्यायाधीश द्वारा इस नीति के निर्माण की बात करता है तो इन पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।"

इससे यह स्पष्ट होगा कि अनुच्छेद में ब्रैकेटेड भाग मध्यस्थता की

सीट पर निर्णय लेने के लिए नहीं था, बल्कि पार्टियों की सुविधा के लिए था, यदि वे सियोल, कोरिया के अलावा कहीं और मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करना चाहते हैं। नेवीरा अमोजोनिका पेरुआना एसए बनाम कंपेनिया इंटरनेशनल डी सेगुरोस डेल पेरू (सुप्रा उद्धृत) के फैसले से ऊपर उद्धृत किया गया हिस्सा इस अनुमान का समर्थन करता है। उस दृष्टि से, मेरा निष्कर्ष यह है-

1. इस मामले में पार्टियों के बीच डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते के अनुच्छेद 22 और 23 की स्पष्ट भाषा अधिनियम के भाग प् को छोड़कर पार्टियों के बीच एक स्पष्ट समझौते को दर्शाती है।

2. भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एसए और अन्य में निर्धारित कानून। (ऊपर उद्धृत) और इंडटेल टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम डब्ल्यूएस एटकिन्स रेल लिमिटेड। (सुप्रा उद्धृत), जैसा कि साइटेशन इन्फोवेयर्स लिमिटेड बनाम इक्विनॉक्स कॉर्पोरेशन (सुप्रा उद्धृत) में भी वर्तमान मामले पर लागू नहीं है।

3. चूंकि अनुच्छेद 23.1 की व्याख्या से पता चलता है कि मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला कानून कोरियाई कानून होगा और मध्यस्थता की सीट कोरिया में सियोल होगी, अधिनियम की धारा 11(6) की प्रयोज्यता और नियुक्ति का कोई सवाल ही नहीं होगा। उस प्रावधान के संदर्भ में मध्यस्थ।

14. ऊपर जो कहा गया है उसके संदर्भ में, याचिका बिना किसी खर्चे के खारिज की जाती है।

मध्यस्थता याचिका खारिज

नोटः- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री मोहित व्यास, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकारणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।